रजिस्टर्ड नं 0 ल 0-33/एस 0 एम 0 14.



राजपत्न, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 24 सितम्बर, 1990/2 म्राश्विन, 1912

हिमाचल प्रदेश सरकार

पंचायती राज विभाग

ग्रधिसूचना

शिमला-171002, 6 सितम्बर, 1990

संख्या पी सी एच-एच ए (1)-42/87.—क्योंकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) ग्रधिनियम, 1987 (1987 का 13) की धारा 2 द्वारा यथा प्रतिस्थापित हिमाचल प्रदेश पंचायती राज ग्रधिनियम, 1968 की धारा 4 की उप-धारा (1) के उपबन्धों के ग्रनुसार ग्राम सभा क्षेत्रों का पुनर्गठन किया जाना ग्रपेक्षित है।

प्रौर क्योंकि ग्राम सभा के क्षेत्रों के पुनगर्ठन की प्रिक्या हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) ग्रिधिनियम, 1987 (1987 का 13) की धारा 3 के ग्रिधीन यथा विहित 3 वर्ष की ग्रविध के भीतर पूर्ण नहीं हो सकी ग्रीर उक्त श्रविध का विस्तारण लोकहित में है।

मूल्य: 1 रुपया।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश सरकार पंचायती राज विभाग की अधिसूचना संख्या पी सी एच-एच ए (3)-5/76-5, दिनांक 5 मई, 1990 का क्रम जारी रखते हुए एवं हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संगोधन) अधिनियम, 1990 (199) का अधिनियमसंख्या 9) की धारा 2 द्वारा यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संगोधन) अधिनियम, 1987 (1987 का 13) की धारा 3 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, तीन वर्ष की अविध को तीन मास की बजाए चार मास विस्तारण करते हैं।

श्रादेश द्वारा, हस्ताक्षरित/-सचिव।

कार्यालय उपायुक्त, जिला किन्मौर, रिकांग पिम्रो

कारण बताम्रो नोटिस

रिकांग पिम्रो, 17 सितम्बर, 1990

संख्या कनर-502/19-1002.—क्योंकि उप सम्भागीय अधिकारी, विकास खण्ड निचार की रिपोर्ट दिनांक 31 अगस्त, 1990 के अन्तर्गत श्री गोविन्द सिंह नेगी, प्रधान, ग्राम पंचायत पौण्डा ने मुवलिक 20,000/- रु0 सहकारी बैंक निचार से पंचायत स्टाल निर्माण भाबानगर हेतु निकालकर उक्त राशि को अपन रिस्तेदार श्री बहादुर सिंह, ग्राम कंगोश वाले को पेशगी दिखाकर उक्त राशि का दुरुपयोग किया है जबिक पंचायत स्टाल का कार्य जो 9/89 को पूर्ण किया जाना चाहिए था आज तक अपूर्ण है।

क्योंकि मुवलिक 2.0,000/- रुपये दिनांक 20-12-1988 से म्राज तक पेशगी दिखाकर ग्राम पंचायत को उक्त राशि पर मिलने वाले ब्याज की राशि से वंचित रखा, साथ ही पंचायत स्टाल समय पर तैयार न किये जाने के कारण जो किराये क रूप में एक वर्ष से भी मधिक समय भ्रविध में म्राय होनी थी उससे पंचायत को वंचित रखा है।

पंचायत स्टाल का कार्य समय पर न किये जाने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा ऋण की किस्त जो 31-3-1990 को मुवलिंग 2,700/- रुपये देय थी को भी कोष में जमा नहीं किया गया।

उपरोक्त से सिद्ध होता है कि श्री गोविन्द सिंह नेगी, प्रधान, ग्राम पंचायत पौण्डा, विकास खण्ड निचार ने मुवलिंग 20,000/- रुपये पेशगी दिखाकर इस राशि का दुरुपयोग किया है तथा समय-समय पर उप सम्भागीय ग्रीधकारी, विकास खण्ड निचार तथा जिला पंचायत श्रीधकारी, रिकांग पिग्रो द्वारा कार्य समय पर पूर्ण करने तथा राशि ब्याज सहित बैंक में जमा करने के लिये दिये गये निर्देशों की पालना भी नहीं की है।

ग्रतः मैं, शक्ति सिंह चन्देल, जिलाधीश किन्नौर, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज ग्रिधिनियम की धारा 54 (1) तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम 1971 के नियम 77 के ग्रन्तगंत यह कारण बताग्रो नोटिस जारी करता हूं कि क्यों न श्री गोविन्द सिंह नेगी, प्रधान, ग्राम पंचायत पौण्डा को प्रधान पद से निलम्बित किया जाए तथा राशि का दुरुपयोग करन पर ग्रिभियोग दर्ज किया जाए।

श्री गोविन्द सिंह नेगी प्रधान, ग्राम पंचायत पौण्डा को इस कारण बताम्रो नोटिस द्वारा निर्देश दिया जाता है कि वह उपरोक्त राशि को व्याज सिंहत तुरन्त बैंक में जमा करें तथा ग्रपना स्पष्टीकरण राशि को दुरूपयोग किय जान का उप सम्भागीय अधिकारी, विकास खण्ड निचार के माध्यम से इस नोटिस के प्राण्ति के 15 दिनों के भीतर प्रघोहरताक्षरी को भेजें। निर्धारित श्रवधि पर उत्तर प्राप्त न होन पर एक पक्षीय कार्यवाही श्रमल में लाई जायेगी।

हस्ताक्षरित/-उपायुक्त, जिला किन्सौर,रिकांग पिश्रो।

कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, बिलासपुर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

प्रधिस्चना

बिलासपुर, 19 सितम्बर, 1990

संख्या एफ0 डी0 एस0 बी0 एल0 पी0-7-181 (म्रापूर्ति)/86-3902-3950 — इस कार्यालय द्वारा जारी म्रधिसचना संख्या एफ0 डी0 एस0 बी0 एल0 पी0-7-181 (म्रापूर्ति)/86-3391-3451, दिनांक 3-8-90 द्वारा म्रावश्यक वस्तुम्रों का ग्रधिकत्तम परचून विक्रय मूल्य निर्धारण किया गया था का प्रसंग जारी रखते हुए जो कि हिमाचल प्रदेश म्रसाध।रण राजपल में दिनांक 25-8-90 को प्रकाशित हो चुकी है तथा हिम।चल प्रदेश जमाखोरी/मुनाफाखोरी निरोधक म्रादेश, 1977 की घारा 3 (1) (ई) के भ्रधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए में, एस0 के0 दास, जिला दण्डाधिकारी, बिलासपुर, जिला बिलासपुर म्रादेश जारी करता हूं कि उपरोक्त म्रधिसूचना द्वारा निर्धारित म्रधिकतम परचून विक्रय मूल्य म्रगले दो माह यानि 23-11-90 बक लागू रहेंगे।

एस० के० दास, ज़िला दण्डाधिकारी, विलासपुर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।